

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे० वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-16/2023-FC दि. 13.06.2023

---0---

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई (xix) बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

S.No	Conditions	Compliance																																							
i	The basic details of proposed dam like its height, length, hydrological assessment etc. along with detailed project report shall be submitted.	<p>इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा बांध से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Morand Dam</th> <th>Ganjal Dam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>The River</td> <td>Morand River</td> <td>Ganjal River</td> </tr> <tr> <td>Catchment area up to dam site</td> <td>1031.99 Sq.kms</td> <td>413.49 Sq.kms</td> </tr> <tr> <td>75 % dependable yield</td> <td>316.34 MCM</td> <td>126.75 MCM</td> </tr> <tr> <td>Maximum probable Flood</td> <td>8795 Cumec</td> <td>4650 Cumec</td> </tr> <tr> <td>Type of Dam</td> <td>Earthen</td> <td>Earthen</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>481 m</td> <td>1145 m</td> </tr> <tr> <td>Maximum Height</td> <td>47.28 m</td> <td>35.067 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Saddle Dam</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>628.00 m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Earthen portion</td> <td>405.98 m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Overflow portion including Key</td> <td>252.25 m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maximum Height</td> <td>21.51 m</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Central water commission has already examined the hydrology and water use of the entire project in details and has approved the same. Water requirement pressure irrigation has been assessed and approved by irrigation planning directorate of CWC. Project has been accurately determined, assessed and approved by the Hydrology Directorate of CWC. Also, various demands on the reservoirs has been pondered over, examined and approved by IP Directorate of CWC, these assessments and approvals are already in record. Hydrology Report Enclosed. (Annexure - 1)</p>	Description	Morand Dam	Ganjal Dam	The River	Morand River	Ganjal River	Catchment area up to dam site	1031.99 Sq.kms	413.49 Sq.kms	75 % dependable yield	316.34 MCM	126.75 MCM	Maximum probable Flood	8795 Cumec	4650 Cumec	Type of Dam	Earthen	Earthen	Length	481 m	1145 m	Maximum Height	47.28 m	35.067 m	Saddle Dam			Length	628.00 m	-	Earthen portion	405.98 m	-	Overflow portion including Key	252.25 m	-	Maximum Height	21.51 m	-
Description	Morand Dam	Ganjal Dam																																							
The River	Morand River	Ganjal River																																							
Catchment area up to dam site	1031.99 Sq.kms	413.49 Sq.kms																																							
75 % dependable yield	316.34 MCM	126.75 MCM																																							
Maximum probable Flood	8795 Cumec	4650 Cumec																																							
Type of Dam	Earthen	Earthen																																							
Length	481 m	1145 m																																							
Maximum Height	47.28 m	35.067 m																																							
Saddle Dam																																									
Length	628.00 m	-																																							
Earthen portion	405.98 m	-																																							
Overflow portion including Key	252.25 m	-																																							
Maximum Height	21.51 m	-																																							

ii	The site specificity of the proposal shall be re-examined and a detailed report along with justification as to why the project cannot be located in non-forest area shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि यह परियोजना Narmada Water Disputes Tribunal (NWDT) से स्वीकृत है। आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि इस बांध स्थल का निरीक्षण Central Water Commission द्वारा करने के उपरांत उनके द्वारा भी बांध स्थल का चयन को अंतिम रूप दिया गया है। अतः आवेदक संस्था द्वारा दिया गया तर्क मान्य योग्य है। विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।
iii	The details of the alternative sites examined along with KML files shall be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रकरण में तीन विकल्पों पर विचार किया गया है। सभी विकल्पों पर विचार करने के उपरांत चयनित स्थल पर बांध की लम्बाई न्यूनतम होने तथा बांध निर्माण हेतु उचित फाउंडेशन मिलने के कारण स्थल का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस विकल्प में न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है। आवेदक संस्था द्वारा तीन विकल्पों का विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न कर प्रस्तुत किया है।
iv	The plan along with details for further distribution of water to end users shall be submitted. In case additional forest land is required for distribution of water, the details of the same shall be provided.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि सिंचाई कार्यों के लिये किसी प्रकार से अतिरिक्त वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में उनके द्वारा स्वीकृत प्लान की प्रति प्रस्तुत की है जो परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।
v	The copy of CAT plan as submitted does not mention that the same is approved by the Principal CCF & HoFF or any other officer authorized by him for the purpose as prescribed under the Chapter-9 at para 9.2(vi) of Comprehensive Guideline Handbook, 2019. The same needs to be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत जल ग्रहण उपचार योजना की तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/41, दिनांक 07.08.2023 से जारी की गई है जिसकी प्रति संलग्न है। जल ग्रहण उपचार योजना की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।
vi	The extant proposal is for an irrigation project, however as per the component wise break up forest land has been proposed to be used for quarrying. The justification for setting up of quarry in the instant irrigation project along with approved mining plan shall be submitted	आवेदक संस्था द्वारा खनन के लिये प्रस्तावित वनभूमि को प्रस्ताव से हटा लिया है। इस खनन क्षेत्र को हटाने के बाद प्रस्ताव में आवेदित वनक्षेत्र का रकबा 2250.05 हेक्टेयर रह जाता है।
vii	The proposal involves the rehabilitation of people and the State Govt. has reported 644 number of families being displaced due to the instant project whereas the DFO, Harda in its Site Inspection Report has reported that 1075 individuals would be displaced. This variation needs to be rectified and actual numbers may be intimated along with the copy of approved R&R plan.	आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में कुल 644 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इन 644 परिवार में कुल 1075 व्यक्ति है। इस प्रकार वनमण्डलाधिकारी, हरदा ने प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 1075 बताई है वह 644 परिवारों में आते हैं। आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि प्रभावित परिवारों का पुर्नविस्थापन Rehabilitation And Resettlement Act, 2013 के अनुसार किया जायेगा।

viii	The CCF, Betul and the CF, Narmadapuram in their Site Inspection report have mentioned that the forest land proposed for diversion forms a part of an active wildlife corridor utilized by wild animals (Tiger, Panther, etc.). The project execution may therefore lead to habitat fragmentation and cause obstruction in the corridor. Therefore, the State Government shall submit the comments of the Chief Wildlife Warden along with availability of alternative wildlife corridors in order to mitigate the detrimental effects of submergence of proposed forest land. It is further required to submit wildlife conservation plan approved by CWLW.	<p>आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है।</p> <p>इस संबंध में इस कार्यालय का यह अभिमत है कि यह योजना औपचारिक स्वीकृति के पूर्व जमा करा दी जायेगी। यदि यह योजना समय पर तैयार नहीं होती है तो भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के लिये आवेदक संस्था से जमा कराई जायेगी।</p>																								
ix	The Cost Benefit analysis has been calculated on the old NPV rates. The same is required to be submitted in the prescribed format keeping in view the latest rates of NPV.	आवेदक संस्था द्वारा पुनरीक्षित Cost Benefit Analysis प्रस्तुत कर दिया गया है जो परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।																								
x	The recommendation of CCF/ CF, Khandwa, Part-III has not been found uploaded online and same shall be uploaded.	मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।																								
xi	As per the project report the total forest area required in the project is 2270.89 ha, the FRA certificate have been issued by the respective district collectors for an area of 2410.335 ha and the online proposal has been submitted for an area of 2272.05 ha. This discrepancy in the area figures shall be examined and factual position shall be intimated.	<p>आवेदक संस्था ने अगवत कराया है कि जब यह परियोजना तैयार की जा रही थी तब प्रभावित वनक्षेत्र का रकबा 2410.335 हेक्टेयर होना प्राक्कलित किया गया था।</p> <p>तत्पश्चात मौके पर सीमांकन में प्रभावित वनक्षेत्र का रकबा वास्तविक रूप से 2272.05 हेक्टेयर पाया गया जिसके लिये आवेदक संस्था द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है।</p> <p>प्रस्ताव में खनन क्षेत्र का रकबा अब हटा लिया गया है जिस कारण प्रभावित वनक्षेत्र का रकबा कम होकर 2250.05 हेक्टेयर ही रह गया है।</p> <p>प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र में उल्लेखित 2410.335 हेक्टेयर में वर्तमान में प्रस्तावित 2250.05 हेक्टेयर वनक्षेत्र सम्मिलित है। अतः नवीन FRA प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p>																								
xii	The instant proposal is for diversion of 2272.05 ha forest land wherein the State Govt. has reported that the project is likely to be executed in a phased manner. Therefore, the phase wise details along with component wise breakup shall be submitted.	<p>आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में वनक्षेत्र निम्नलिखित कार्यों के लिये आवश्यक होना प्रतिवेदित किया है :-</p> <table border="1" data-bbox="852 1529 1453 1964"> <thead> <tr> <th>S No.</th> <th>Phase</th> <th>Component</th> <th>Proposed area in Ha.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>First</td> <td>Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line</td> <td>116.27</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Second</td> <td>(FRL-4)</td> <td>1135.57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Third</td> <td>(FRL-4)</td> <td>616.748</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fourth</td> <td>(FRL)</td> <td>381.462</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>2250.05</td> </tr> </tbody> </table>	S No.	Phase	Component	Proposed area in Ha.	1	First	Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line	116.27	2	Second	(FRL-4)	1135.57	3	Third	(FRL-4)	616.748	4	Fourth	(FRL)	381.462			Total	2250.05
S No.	Phase	Component	Proposed area in Ha.																							
1	First	Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line	116.27																							
2	Second	(FRL-4)	1135.57																							
3	Third	(FRL-4)	616.748																							
4	Fourth	(FRL)	381.462																							
		Total	2250.05																							

<p>xiii</p>	<p>It has been informed that the District Collectors, Sagar, Betul, Agar Malwa and Jabalpur have reserved land for carrying out CA in the instant proposal. However, after examination of the same it has been found that as per District Collector, Betul vide their order dated 25.09.2018 an area of 662.00 ha of land has been reserved for CA out of which an area of 386.469 ha is proposed for CA against the instant proposal in Tehsil Betul, Amla and Godhadungri. However the land type of proposed CA is recorded as Forest land, Bade Jhar ka Jungle. Also as per District Collector, Sagar vide their order dated 18.09.2018 an area of 1071.99 ha of land has been reserved for CA and same is proposed for CA against the instant proposal. However the land type of proposed CA in Tehsil Kesli, Village - Padhna Khurd, Chirai, Rengajholi is recorded as Government Forest land. Further the land type (Bhumi Noiyath) of CA land is not recorded in District Collector, Jabalpur order dated 18.02.2019. Therefore, the State Government shall clarify that whether such lands proposed for CA does not comes in the ambit of Forest (Conservation) Act, 1980 and justify these lands as NFL.</p>	<p>प्रकरण में आवेदक संस्था ने क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये अलग-अलग जिलों में गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है। इस गैर वनभूमि का अभी आधिपत्य एवं रोपण योजना अभी नहीं बनाई गई है। प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही चाही गई है। अतः इसके समतुल्य गैर वनभूमि का आधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है। आवेदक संस्था द्वारा अन्य चरणों में जितनी वनभूमि चाही गई है, उसके समतुल्य गैर वनभूमि का आधिपत्य तत्समय प्राप्त कर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक चरण में इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। ऐसा करना इसलिये भी उचित होगा क्योंकि यदि गैर वनभूमि का आधिपत्य अभी प्राप्त कर लिया जाता है तो इसमें अतिक्रमण होने की सम्भावना बनी रहेगी।</p>
<p>xiv</p>	<p>The approved CA scheme along with site suitability certificates from the concerned DFO shall be submitted.</p>	<p>बिन्दु क्रमांक (XIII) में दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही चाही गई है। अतः इसके समतुल्य गैर वनभूमि का आधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है।</p>
<p>xv</p>	<p>As per DSS analysis, it has been observed that:</p>	
<p>a</p>	<p>The area of forest land proposed for diversion is found to be 1923.313 ha instead of 2272.05 ha as proposed. Therefore, the correct KML file as per the proposal needs submission.</p>	<p>आवेदक संस्था द्वारा संशोधित KML फाईल प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।</p>
<p>b</p>	<p>High resolution satellite imagery shows the presence of Agricultural land and Settlements within the forest patches sought for diversion. Why such settlements and land use may not be considered as violation. This needs clarification.</p>	<p>प्रस्तावित वनक्षेत्र में कई वनाधिकार पट्टाधारी है। इन पट्टाधारियों को नियमानुसार आवेदक संस्था के व्यय पर विस्थापित किया जायेगा। आवेदित वनक्षेत्र में अवैध अतिक्रमकों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार बेदखल किया जायेगा।</p>
<p>c</p>	<p>The complete KML file of submergence area/ Non-forest land involved in the project i.e. 1277.694 ha on the PARIVESH portal. The same needs submission.</p>	<p>आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित 1277.694 हेक्टेयर गैर वनभूमि की KML फाईल आनलाईन भाग-1 के बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वनमण्डल खण्डवा की टेबल में बिन्दु क्रं.-2 मे 0 हेक्टे. के रूप में अपलोड की गई है।</p>

d	The total area of proposed CA land through KML file is found 2540 ha whereas the State Govt. reported CA area of 2407.189 ha. Therefore, the State Govt. shall provide the correct KML file of CA area as per the actual records/ orders	बिन्दु क्रमांक (XIII) में दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही चाही गई है। अतः इसके समतुल्य गैर वनभूमि का आधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है।
e	Satellite imagery shows the presence of Settlements/ Built-up in the CA areas located in Villages jaitpur kachhaya (35 ha) & Danger salaiya (100 ha). Moreover, an earthen dam also exists within the proposed CA site at village Danger salaiya. This needs clarification.	
f	Satellite imagery shows the presence of Settlements/ Built-up, Agriculture land, earthen dam, Road, play ground in the entire CA sites proposed in Village Chirrari. This needs clarification.	
g	Satellite imagery shows the presence of earthen dam and canals at the CA sites proposed in villages Bhuhara, Chak vileki and Vileki. Moreover, presence of Agriculture land can also be seen in the 601.58 ha land proposed for CA. This needs clarification.	
h	Part of CA site is falling on the submergence of an earthen dam, having the presence of settlements/ town, construction of check dam is also going on in the proposed CA site. Moreover, part of mined out area is also visible within the proposed CA site at village Khamkua. This needs clarification.	
i	Presence of Settlements and Agriculture land can be seen at proposed CA site at Village Sahajpuri kalan. This needs clarification.	
j	An earthen dam is located within the proposed CA site at Village Tirmahu. This needs clarification.	
k	All proposed CA site at Villages Gopalpura, Gandhigram, Sukadhana, Sobhapur, Pandra, Bodna, Mordongri and Chapada rayat are having presence of Agriculture land and an earthen dam with settlements over 44 ha CA site. Moreover, plantation works are visible within the 60 ha area of proposed CA site. This needs clarification.	
l	Mining is going on near the proposed CA site village Barguwan. Therefore, the State Govt. shall ensure that the proposed CA site is the not the part of Mine lease.	
m	Part of proposed CA site at Village Shyampura & Garda are having presence of settlements within the CA boundary. Moreover, part of proposed CA land is also falling on the submergence zone of existing earthen dam. This needs clarification.	
n	Plantation work and some pre-plantation operations are visible within the proposed CA Site at Village Dongargaon & Bid Madhopur. Moreover, part of CA site at village Dongargaon is falling on the submergence zone of an earthen dam. This needs clarification.	
o	It is also learnt the user agency/ State Govt. has uploaded many KML files of the CA land in the line feature instead of Polygon on the PARIVESH. Further, proper annotation/ attributes to each KML file of CA land has not been mentioned due to which it is very difficult to identify and locate CA land KML file with respect to their villages & Khasra Nos. The same shall be resubmitted and rectified.	

xvi	The proposed CA area are not free from encumbrances as per above observations from DSS analysis. A justification may be provided for identifying such land and State Government may comment that is there any requirement for rehabilitation & resettlement of people from the identified CA lands.	बिन्दु क्रमांक (XIII) में दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम चरण में 116.27 हेक्टेयर वनभूमि ही चाही गई है। अतः इसके समतुल्य गैर वनभूमि का आधिपत्य जबलपुर जिले में प्राप्त कर रोपण योजना तैयार की गई है।
xvii	The State shall also specifically mention the plan to protect the identified CA land from encroachment in future. A detailed plan shall be submitted accordingly.	इस प्रस्ताव में आवेदक संस्था से चरणवार आवश्यक वनभूमि के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वनभूमि प्राप्त की जायेगी। इसके पूर्व जल संसाधन विभाग के छीताखुदरी (69.555 हेक्टे. वनभूमि) तथा हिरन (54.87 हेक्टे. वनभूमि) परियोजनाओं में भी क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये ली जाने वाली गैर वनभूमि को चैनलिंग फेंसिंग कर प्राप्त करने की शर्त भारत सरकार द्वारा अधिरोपित की गई थी। इसी प्रकार इस प्रकरण में भी आवेदक संस्था से क्षतिपूर्ति वनीकरण की गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर तथा चैनलिंग फेंसिंग करवाकर प्राप्त की जावेगी।
xviii	The complete lay out plan along with KML files indicating all the components like canal, Quarry Area etc. shall be submitted.	आवेदक संस्था ने परियोजना का लेआउट प्लान प्रस्तुत किया है, जो परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।
xix	As per the technical approval dated 18.10.2017 it has been mentioned that the Morand Dam will be constructed in Phase-I and if the water requirement gets fulfilled by the same in that case the construction of Ganjal will not take place. Moreover the Indira Sagar Dam is located at a distance of 54.40 Km from the proposed forest diversion site for Harda Dam and Tawa Reservoir is located at a distance of 34.33 Km from the proposed forest diversion site for Morand Dam. In this regard, specific reasons for proposing the construction of instant dams are required.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस गंजाल बांध निर्माण के उपरांत भी काफी क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वंचित रहेगा। अतः राज्य शासन द्वारा दोनों बांध निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 31-21/2017/सत्ताईस-एक, दिनांक 21/04/2022 से इसकी स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16-8-23

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/3670
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त होशंगाबाद/वृत्त खण्डवा/वृत्त बैतूल/वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, हरदा/होशंगाबाद/खण्डवा/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल